सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

जल है तो कल है

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-5 • 01 SEPTEMBER TO 07 SEPTEMBER 2023 • VOLUME 6 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

बात तो केवल विश्वास की है वरना एक छोटे से ताले के भरोसे हम अपना लाखों का कीमती सामान कैसे छोड़ सकते थे।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay Money after the visa

•IELTS •STUDY ABROAD

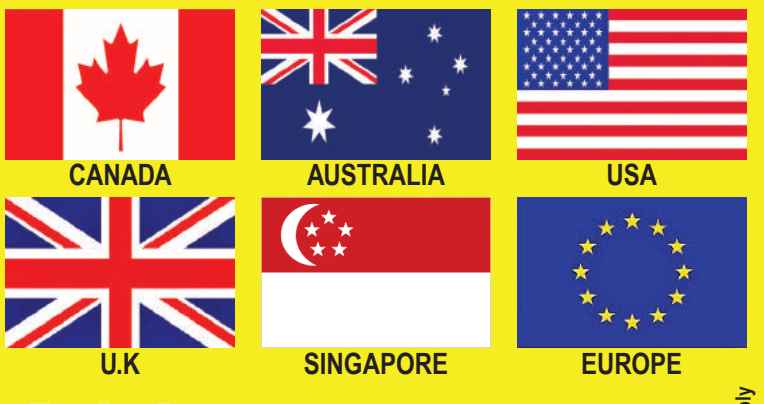

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.

*T&C apply

18 से 22 सितंबर को बुलाया गया संसद का विशेष सत्र

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा- संसद के इस विशेष सत्र में होंगी पांच बैठकें

नई दिल्ली. अमृत काल के बीच संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है जिसमें पांच बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है।

संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि यह सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में जी20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अमृत काल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में

सार्थक चर्चा को लेकर आशान्वित हैं।

कांग्रेस ने सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने के फैसले के बाद बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि अडाणी समूह के खिलाफ नये खुलासे होने और विपक्ष की बैठक के चलते समाचारों का प्रबंधन करने की कवायद के तहत विशेष सत्र की घोषणा गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस विशेष सत्र के दौरान भी अडाणी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग सदन के भीतर और बाहर जारी रहेगी।

विपक्षी नेताओं ने जताई ये आशंका : ऐसे समय में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है जब पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेता समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जता चुके हैं।

ये बिल हैं अहम : स्पेशल सेशन बुलाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) और महिला आरक्षण से जुड़े बिल अहम माने जा रहे हैं।

पंचायतें भंग के मामले में सरकार का यू-टर्न

लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा- तकनीकी ख़ामियों के कारण वापस लिया फैसला

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज कहा कि लोकतंत्र की नींव कही जाती पंचायतों

को भंग करने सम्बन्धी फ़ैसला तकनीकी ख़ामियों के कारण वापस लिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंचायतों को भंग करने का मामला जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के संज्ञान में आया तो उन्होंने तकनीकी ख़ामियों के कारण तुरंत पंचायतों को भंग करने के आदेशों के लिए पंचायती विभाग के अफ़सरों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने के आदेश दिए एवं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायतों को भंग करने वाला फ़ैसला वापस ले लिया गया ताकि तकनीकी खामियों को पूरा करके मतदान बिना किसी पक्षपात से हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में गाँवों की पंचायतों के चुनाव समय पर करवाने के लिए प्रयास शुरू किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए वोटर सूचियों में संशोधन, वार्डबन्दी और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण आदि की प्रक्रिया काफ़ी लम्बी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में आई बाढ़ के कारण अफ़सरों और कर्मचारियों के लोगों की सहायता के लिए व्यस्त होने के कारण यह कार्य अपूर्ण ही रह गया था।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पंचायती चुनाव को समय पर करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंचायती चुनावों सम्बन्धी और लोकतंत्र को मज़बूत करने सम्बन्धी यह भी ऐलान किया है कि जो गाँव सर्व-सहमति से पंचायतों की चयन करेंगे, उनको 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। पंजाब सरकार ने पंचायतें भंग करने सम्बन्धी तकनीकी ख़ामियों वाला फ़ैसला लेने वाले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव और डायरैक्टर को तुरंत प्रभाव के साथ निलंबित कर दिया है।

दो आईएएस अधिकारी सस्पेंड

पंचायतें भंग करने के मामले में दो आईएएस अधिकारियों पर गाज गिरी है। एक आईएएस का नाम धीरेन्द्र कुमार तिवारी है जिनकी तैनाती पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में थी। वहीं, दूसरे आईएएस का नाम गुरप्रीत सिंह खैरा है जिनकी तैनाती पंचायत विभाग में बतौर निदेशक थी। गुरूवार सुबह ही पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में मान सरकार ने जानकारी दी थी कि पंचायत भंग नहीं की जा रही हैं।

5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए माइनिंग विभाग का ऐक्सियन और एसडीओ काबू

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने माइनिंग विभाग के एक कार्यकारी इंजीनियर (ऐक्सियन) और एक उप मंडल अधिकारी (एसडीओ) को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू किया है। काबू किए गए मुलज़िमों की पहचान होशियारपुर में तैनात ऐक्सियन सरताज सिंह रंधावा और दसूहा के एसडीओ हरजिन्दर सिंह के रूप में हुई है। विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि जगराओं तहसील के गाँव ढोलन निवासी जसप्रीत सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह रीगल एंटरप्राईजिज़ कंपनी में साइट कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। कंपनी को मुकेरियाँ-तलवाड़ा रेलवे लाईन पर मिट्टी डालने का ठेका मिला था और कंपनी ने दसूहा तहसील के गाँव घगवाल से मिट्टी उठाने के लिए सम्बन्धित विभाग के पास सरकार द्वारा निर्धारित फीस 41,10,117 रुपए भी जमा करवा दिए थे। इसके उपरांत उनके संज्ञान में आया कि जिस ज़मीन के लिए उन्होंने फीस अदा की है, वह ज़मीन वन विभाग की धारा 4 और 5 के अधीन आती है। कंपनी ने मार्च 2023 में रॉयलिटी तबदील करने के लिए आवेदन दिया था। शिकायतकर्ता अपने सीनियर जतिन्दर सिंह को साथ लेकर 20 जुलाई को उक्त एक्सियन और एसडीओ को दफ्तर में मिले। एक्सियन सरताज रंधावा ने कहा कि रॉयलिटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, परन्तु बार-बार विनती करने पर ऐक्सियन ने कहा कि इस संबंधी एसडीओ हरजिन्दर सिंह उनके साथ बात करेगा। शिकायतकर्ता ने दोष लगाया कि कुछ दिनों के उपरांत मुलजिम एसडीओ ने जतिन्दर सिंह को दसूहा स्थित अपने दफ्तर बुलाया और बताया कि ऐक्सियन सरताज रंधावा ने रॉयलिटी ट्रांसफर करने के बदले 12 लाख रुपए की रिश्वत माँगी है। बाद में मुलजिम एस.डी.ओ. 8 लाख रुपए में राज़ी हो गया। शिकायत की प्राथमिक जांच के उपरांत प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस ब्यूरो यूनिट, होशियारपुर की टीम ने ट्रैप लगाकर दोनों मुलजिमों को सरकारी गवाहों की हाजिऱी में शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू कर लिया।

उन्होंने बताया कि ऐक्सियन सरताज रंधावा और एसडीओ हरजिन्दर सिंह के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आई.पी.सी की धारा 34 के अधीन थाना विजीलैंस ब्यूरो, जालंधर रेंज में तारीख़ 31-08-2023 को एफ.आई.आर नं. 22 के अंतर्गत दर्ज की गई है। दोनों मुलजिमों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जायेगा।

आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा के 6 साथी गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) ने एस.ए.एस. नगर पुलिस के साथ साझे ऑपरेशन के दौरान आईएसआई की सहायता प्राप्त पाकिस्तान आधारित आतंकवादी हरविन्दर सिंह उर्फ रिन्दा के 6 साथियों को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से पाँच पिस्तौलों समेत गोला-बारूद बरामद किया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रोशन कुमार, सौरब कुमार, विक्रम कुमार, अमरिन्दर सिंह उर्फ बिल्ली, अर्शवीर सिंह और सन्नी, सभी निवासी पटियाला, के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए सभी मुलज़िम कत्ल, इरादात कत्ल, जबरन वसूली, डकैती, हथियारों की अंतरराज्यीय तस्करी आदि समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।

रैवेन्यू कर्मचारियों की 'पेनडाउन स्ट्राइक' आज से

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बुधवार को प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया है। प्रदेश सरकार की इस घोषणा के बाद पटवारियों ने घोषणा की है कि वे शुक्रवार यानी 1 सितंबर से पेनडाउन स्ट्राइक शुरू करेंगे।

दी रेवन्यू पटवार यूनियन के अध्यक्ष ने इस संबंध में कहा कि पंजाब के 4 हजार 716 पटवार सर्कल्स में से 3 हजार 193 पद खाली पड़े हैं। मौजूदा समय में 1 हजार 523 पटवारी ही इन पटवार सर्कल्स में एडिशनल के तौर पर काम कर रहे था। मगर शुक्रवार से से पटवारी इन खाली पड़े सर्कल्स में कोई काम नहीं करेंगे और सिर्फ अपने सर्किल का ही काम देखेंगे।

खेडां वतन पंजाब दियां-2023 के ब्लॉक स्तरीय मुकाबलों की हुई शुरुआत

आठ खेलों में आठ उम्र वर्गों के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले 31 अगस्त से 9 सितम्बर तक चलेंगे

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा बठिंडा में उद्घाटन समारोह के दौरान 'खेडां वतन पंजाब दियां- 2023' (सीजन-2) के शानदार आग़ाज़ के बाद आज ब्लॉक स्तरीय मुकाबलों की शुरुआत हो गई। आज राज्य भर के 157 ब्लॉकों में आठ खेलों में मुकाबले शुरू हो गए और डेढ़ लाख से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने समूह ज़िला खेल अफसरों को हिदायत की है कि जो खिलाड़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके परन्तु वह ग्राउंड में पहुँचते हैं तो उनको भी हिस्सा दिलाया जाये। कई खिलाडिय़ों द्वारा यह माँग की जा रही थी कि वह किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, इसलिए खेल मंत्री द्वारा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला किया गया है। खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि इस बार कुल 35 खेलों में आठ उम्र वर्गों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इनमें से आठ खेलों के मुकाबले ब्लॉक स्तर से शुरू हो गए हैं।

जंगलों में आग की घटनाएं : जी-20 के माध्यम से प्रत्युत्तर की तैयारी

जालंधर ब्रीज. पिछले कुछ दशकों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में काफी तेजी आई है। इन घटनाओं से कनाडा के बोरियल जंगलों और ब्राजील के अमेजोन के वर्षा वनों जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्बन सिंक क्षेत्रों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। मार्लीलैंड विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में पाया गया कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं के कारण अब 2001 की तुलना में, प्रति वर्ष 3 मिलियन हेक्टेयर अधिक वृक्षों को नुकसान हो रहा है, जो पिछले 20 वर्षों में सभी वृक्षों के नुकसान की तुलना में एक-चौथाई से अधिक है। आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति, तीव्रता और भौगोलिक प्रसार में इस खतरनाक वृद्धि ने पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव और मानव गतिविधियों की क्षमता के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है।

डॉ. के. रविचंद्रन,
निदेशक, आईआईएफएम

जलवायु परिवर्तन के कारण आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 150 साल पहले की तुलना में गर्म हवाओं (हीट वेव) की तीव्रता पांच गुना अधिक हो गई हैं। इस प्रकार भूसंरचना का निर्जलीकरण होने से जंगलों में आग लगने की और भी अधिक घटनाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।

भारत की स्थिति : भारत ने अपने क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर निगरानी प्रणालियों का विस्तार करके विश्व भर में जंगलों में आगजनी के बढ़ते मामलों की रोकथाम की दिशा में पहल की है। भारत के 25 प्रतिशत जंगल आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, लेकिन केवल 3 प्रतिशत वृक्ष आवरण का नुकसान जंगल की आग के कारण होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने आगजनी की बड़ी घटनाओं की तत्काल एवं निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग के लिए जंगल की आग से संबंधित डेटा को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरैक्टिव दृश्य प्रदान करने के लिए वन अग्नि जियो-पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल भारत में जंगल की आग से संबंधित जानकारी के लिए एकल बिंदु स्रोत के रूप में काम करेगा।

जंगल की आग का प्रबंधन जल्द ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दायरे में होगा, जिससे जंगल की आग का प्रभावी तौर पर तत्काल प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।अधिकारियों की ओर से तकनीकी और नियामक उन्नयन के अलावा जंगल की आग की प्रबंधन रणनीति को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए सामूहिक कार्रवाई के उपायों को अपनाया जा रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) का उपयोग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए किया गया है। सुरक्षा और संरक्षण को लेकर गतिविधियों के विस्तार के लिए देश भर में ग्रामीण स्तर पर जेएफएम समितियां स्थापित की गई हैं। वर्तमान में पूरे देश में 36,165 जेएफएम समितियां हैं, जो 10.24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं।

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय-आधारित अग्नि प्रबंधन से जुड़ी कार्य प्रणालियां लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। इन कार्य प्रणालियों में जागरूकता कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटकों, घर-घर अभियान, अग्नि नियंत्रण कक्ष और वॉच टावरों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण शामिल है। वन विभाग ने एक वर्ष के भीतर अलर्ट में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी का अनुभव किया गया, और जंगल की आग से जले हुए क्षेत्र में 58 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य को अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया है। जिसमें घटिया स्तर का वृक्षारोपण को हटाने की कार्य प्रणालियों को मिट्टी द्वारा सुरक्षित करना और वृक्षारोपण प्रजातियों और वयस्क पेड़ों की कुशल बंडलिंग शामिल है। इससे 12-18 महीनों के भीतर जैव विविधता के घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारत मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और मौसमी घटनाओं को देखते हुए जंगल की आग के प्रबंधन से निपटने की तैयारी कर रहा है। भारत के पारंपरिक जंगल की आग पर नियंत्रण और इसकी प्रभावशीलता का सम्मान करते हुए, भारत लगातार अपनी पारंपरिक विशेषज्ञता को बढ़ावा दे रहा है और अनेक उपायों को अपना रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप जंगल की आग की घटनाओं और उनसे होने वाले नुकसान में कमी आई है। भारत जंगल की आग पर जल्द से जल्द प्रत्युत्तर देने के लिए स्थानीय समुदाय की ताकत पर भरोसा करते हुए समुदाय-आधारित जंगल की आग के प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। साथ ही, निवारक कार्रवाई और आग की घटनाओं के बाद प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में फील्ड प्रबंधकों की सहायता के लिए आधुनिक तकनीक, जैसे अग्नि चेतावनी प्रणाली, जीपीएस ट्रैक द्वारा वन अग्नि के प्रबंधन और पुनरुद्धार आदि को शामिल किया जा रहा है, ताकि आग की घटनाओं और उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

जी20 का महत्व: जलवायु परिवर्तन पर जंगल की आग के प्रभाव के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष जी20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता ने जी20 वैश्विक भूमि पहल को मजबूत करने के लिए 'गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप (जीआईआर) और गांधीनगर सूचना मंच (जीआईपी)' लॉन्च किया। रोडमैप का उद्देश्य वन अग्नि प्रभावित क्षेत्रों और खनन प्रभावित क्षेत्रों की इकोसिस्टम के पुनरुद्धार संबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए भागीदार देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है।

यह जी-20 की भारत की अध्यक्षता द्वारा शुरू किया गया एक अनूठा प्रयास है। जी-20 सदस्यों की एक सहज समझ है कि जलवायु संकट को हल करने के लिए पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर सामूहिक कार्रवाई के प्रयास करने होंगे और यथासंभव परिवर्तन को एक संभावना बनाने के लिए वैश्विक परिदृश्य में प्रभावी ढंग से साझा करना होगा। जीआईपी-जीआईआर पहल की अनिवार्य प्रकृति यह है कि यह रणनीतिक रूप से सामुदायिक भागीदारी और स्वदेशी ज्ञान साझाकरण और तकनीकों के साथ स्थायी वानिकी से संबंधित कार्य प्रणालियों के सक्रिय कार्यान्वयन पर ध्यान देगी। इससे न केवल विभिन्न देशों के बीच स्थिरता आधारित सहकारी संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रवाह को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। इससे पुनरुद्धार से जुड़े क्रियाकलापों के विस्तार में भी मदद मिलेगी।

बेहद खूबसूरत है भारत का आखिरी गांव, जानिए यहां जाने का बेस्ट समय और पहुंचने का तरीका

TRAVELING

माणा भारत का आखिरी गांव है, जहां पर आपको बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिल जाएंगे। यहां जानिए इस गांव में जाने का सही समय और पहुंचने का बेस्ट तरीका।

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

घुमक्कड़ लोग हमेशा अलग-अलग जगहों को एक्सप्लोर करने की चाह रखते हैं। अगर आप किसी नई और शांत जगह की तलाश में हैं तो माणा गांव जा सकते हैं। इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। ये गांव बेहद खूबसूरत है जहां धार्मिक स्थल, समृद्ध नदियां और झरने हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग का रास्ता यहीं से जाता है और यही वह जगह है जहां से पांडवों ने अपनी अनंत यात्रा का मार्ग अपनाया था। अगर आप भारत के इस आखिरी गांव में जाना चाहते हैं तो यहां जानिए पहुंचने का तरीका और यहां जाने का बेस्ट टाइम-

कैसे पहुंचे माणा

भारत का अंतिम गांव माणा तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सड़क मार्ग है, जो एनएच-58 है। गांव तक पहुंचने के लिए आप बद्रीनाथ से शेयरिंग या पर्सनल टैक्सी ले सकते हैं। वहीं माणा से सबसे पास हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। वहीं सबसे पास रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में है।

माणा जाने का बेस्ट समय

माणा गांव की यात्रा केवल गर्मियों और मानसून के मौसम में ही की जा सकती है, जब बद्रीनाथ यात्रा खुलती है। दरअसल, सर्दियों के दौरान यहां भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में गांव माणा की यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच है, हालांकि, सुनिश्चित करें कि आप भारी बारिश के दौरान यात्रा से बचें क्योंकि इस दौरान यहां काफी फिसलन होती है।

FASHION+

व्हाइट ड्रेस में अनन्या पांडे को देख हो जाएंगे फैन, फिल्मी प्रमोशन के लिए था ऐसा लुक

अनन्या पांडे अपने फैशन सेंस से इन दिनों फैंस को इंप्रेस कर ले रही हैं। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के प्रमोशन के लिए निकली अनन्या ने सफेद रंग की मिनी ड्रेस के साथ बूट्स को मैच किया है।

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

अनन्या पांडे हर फिल्म के साथ ही अपने लुक्स पर भी काम कर रही हैं। तभी तो फैशन च्वॉइस के मामले में बहुत कम ऐसा होता है कि वो फीकी लगें या फिर अपने फैंस को निराश। ड्रीम गर्ल 2 के प्रमोशन के दौरान लगातार उनके आउटफिट ने स्टाइलिश गर्ल्स का ध्यान खींचा। तो अगर आप ब्वॉयफ्रेंड के साथ आउटिंग के लिए किसी हटके और सेसी लुक की तलाश में हैं तो अनन्या पांडे के इस लुक को ट्राई कर सकते हैं।

शार्ट ड्रेस में दिख रहीं ग्लैमरस

अनन्या पांडे फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के प्रमोशन के लिए एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ निकली हैं। जहां उनका स्टाइलिश लुक अट्रैक्ट कर रहा है। अनन्या ने सफेद रंग की मिनी ड्रेस कैरी की है। जिसकी राउंड नेक और स्लीवलेस डिजाइन परफेक्ट लग रही थी। वहीं नेकलाइन और स्लीवलाइन पर की गई ब्लू कलर की डिटेलिंग इसे स्पोर्टी लुक दे रही है। इसके साथ ही ड्रेस के बस्ट एरिया पर क्वीन प्रिंट है।

व्हाइट बूट के साथ किया मैच

अनन्या ने इस लुक को स्पोर्टी बनाने के लिए सफेद रंग के एंकल लेंथ बूट्स को पेयर किया था। वहीं स्लीक पोनीटेल परफेक्ट दिख रही थी। बात करें मेकअप की तो पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक और रोज पिंक ब्लश चिक्स के साथ आंखों को काजल के साथ कंप्लीट किया गया था। जो कि उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा था।

प्याज-टमाटर डालकर तैयार होती है स्पॉट इडली, आप भी ट्राई करें ये रेसिपी

इडली में कई तरह की वैरायटी तैयार की जा सकती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर हैदराबादी स्पॉट इडली की रेसिपी वायरल हो रही है। इडली की इस रेसिपी को आप भी ट्राई कर सकते हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

नाश्ते या फिर लंच में इडली काफी अच्छी लगती है। इसे डायट फूड में भी गिना जाता है, हालांकि डायट वाली इडली सूजी से बनाई जाती है। इडली को कई तरह से तैयार कर सकते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर स्पॉट इडली की रेसिपी जमकर वायरल हो रही है। हैदराबाद में खाई जाने वाली ये इडली स्वाद में जबरदस्त लगती है। इसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं। यहां जानिए इसे बनाने का तरीका-

स्पॉट इडली के लिए सामग्री

- मक्खन
- प्याज
- टमाटर
- शिमला मिर्च
- नमक
- मिर्च पाउडर
- धनिया
- इंस्टेंट बैटर
- गन पाउडर

बनाने की रेसिपी

- हैदराबादी स्पॉट इडली बनाने के लिए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को बारीक काट लें।
- फिर तवे को गर्म करें और इस पर बटर को पिघलाएं।
- अब इसपर सारी चीजों को डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकाएं।
- बैटर डालने के बाद तेल डालें ताकि यह अच्छी तरह पक जाए।
- अब नॉन-स्टिक पैन का इस्तेमाल करें ताकि बेस चिपके नहीं।
- अब दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं।

3 साल से ऊपर के बच्चों को खिलाएं ये हेल्दी चीज़ें, आसानी से खा जाएंगे

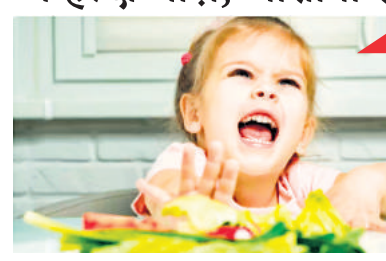

PARENTING

बच्चे जब 2 साल के हो जाते हैं तो उन्हें पूरे दिन कुछ ना कुछ खाने की जरूरत होती है। जिससे उन्हें एनर्जी और पोषण मिले। ऐसे में ये 5 हेल्दी स्नैक्स बेस्ट ऑप्शन हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

बच्चे जब दो से तीन साल के होने लगते हैं तो उन्हें हर वक्त कुछ टेस्टी खाना चाहिए होता है। दाल, रोटी को एक बार खाने के बाद दोबारा खाना पसंद नहीं करते। ऐसे में उन्हें दिनभर अलग-अलग और हेल्दी चीजों को खिलाना जरूरी होता है। जिससे उन्हें जरूरी पोषण मिलने के साथ ही एनर्जी भी भरपूर मिले। बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन खोज रही हैं तो इन हेल्दी रेसिपी को जरूर याद रखें। जो आपके बच्चे को जरूरी न्यूट्रिशन और एनर्जी दोनों भरपूर मात्रा में देगा।

पनीर टिक्की

पनीर को मैश कर उसमे नमक, चाट मसाला और मनचाही सब्जियों को घिसकर डालें। फिर इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर गोल आकार दें और हथेलियों से चपटा कर लें। पैन पर थोड़े से बटर में इसे सेंक लें। ये स्नैक्स बच्चों का पेट भरने में मदद करेगा और उन्हें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा।

बनाना पैनकेक

केला हेल्दी फ्रूट है जिसे बच्चे खूब पसंद करते हैं। आप चाहें तो केले से पैनकेक बना सकती हैं। केले को मैश कर इसमे गेहूं का आटा मिलाएं और दूध डालकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। नॉनस्टिक पैन पर छोटे-छोटे पैनकेक तैयार करें।

एग टोस्ट

अंडे को फोड़कर उसमे नमक और काली मिर्च मिक्स करें। इस बैटर में ब्रेड को डुबोएं और तवे पर सेकें। बच्चे इसे चाव से खाएंगे और ये हेल्दी स्नैक्स है।

चीज सैंडविच

छोटे बच्चों को चीज सैंडविच बनाकर भी दिया जा सकता है। ब्रेड पर चीज की स्लाइस लगाकर सेंकें। ये हेल्दी स्नैक्स और इससे बच्चों का पेट भी भर जाता है।

रोस्टेड नट्स

देसी घी में मखाना, काजू, बादाम, मूंगफली जैसे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रख लें। ये हेल्दी स्नैक्स बच्चों की छोटी-छोटी भूख को शांत करने में मदद करेगा।

बिना शराब पिए भी लिवर हो रहा इन कारणों से खराब, बचाव के उपाय

HEALTH CARE

इन दिनों खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान की आदतों की वजह से बहुत सारे लोग फैटी लिवर जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जिसके बारे में देर से पता चलने से लिवर के डैमेज का खतरा रहता है।

• **जलंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

इंसान के शरीर के जरूरी अंगों में से एक लीवर भी है। जिसका काम शरीर को फिट रखने का है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए शराब ना पीने की सलाह दी जाती है। क्योंकि शराब लिवर का सबसे बड़ा दुश्न है। लेकिन बिना शराब पिए ही लोग फैटी लिवर के शिकार हो रहे हैं। इसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं। जिसमे शराब का सेवन किए बिना ही लिवर के आसपास फैट का डिपॉजिट हो रहा है। जिसका कारण गलत खानपान और लाइफस्टाइल है। आंकड़ों के मुताबिक नॉन एल्कोहलिक लिवर डिसीज लिवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण है।

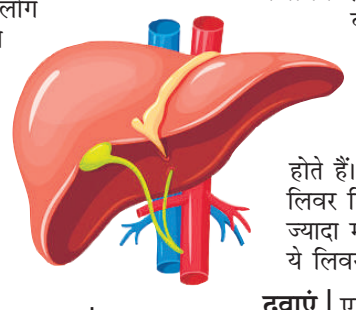

क्या है नॉन एल्कोहलिक लिवर डिसीज | नॉन एल्कोहलिक लिवर डिसीज में लिवर के आसपास फैट जमा होने लगता है। जिसका कारण मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। फैटी लिवर का अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से सूजन और लिवर के डैमेज होने का खतरा रहता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक करीब 15-20 प्रतिशत लिवर ट्रांसप्लांट की वजह फैटी लिवर की वजह से फेल हुए लिवर हैं। आगे जानें फैटी लिवर होने की क्या है वजह।

मोटापा या ओबेसिटी | बहुत ज्यादा मात्रा में मोटापा या फिर केवल पेट के आसपास जमा चर्बी फैटी लिवर के खतरे को बढ़ा देती है।

इंसुलिन रेजिस्टेंस | जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है और इंसुलिन का लेवल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तरह की कंडीशन है जिसमे बॉडी सेल्स इंसुलिन के प्रति रिस्पांस करना बंद कर देते हैं। ये समस्या भी ज्यादातर मोटापे की वजह से ही होती है और लिवर के आसपास फैट जमा होने लगता है।

अचानक से वजन घटना | स्लिम रहने के लिए बहुत सारे लोग क्रैश डाइट को फॉलो करते हैं। जिसकी वजह से वजन तेजी से गिरता है। वजन कम करने का ये तरीका जरा भी हेल्दी नही है बल्कि इससे सेहत को काफी सारे नुकसान होते हैं। क्रैश डाइट की वजह से भी फैटी लिवर डिसीज हो जाती है। क्योंकि फैट टिश्यूज ज्यादा मात्रा में फैटी एसिड बनाने लगते हैं और ये लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं।

दवाएं | एचआईवी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाईयां फैटी लिवर का कारण बनती है।

इन बीमारियों में रहता है फैटी लिवर का खतरा | पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस, हाइपोथायराडिज्म और विल्सन डिसीज में लिवर में फैट जमा होने का खतरा रहता है।

अनहेल्दी डाइट | अनहेल्दी डाइट जिसमे सैचुरेटेड फैट, रिफाइंड फ्लोर, कार्बोहाइड्रेट, शुगर की वजह से लिवर के फैटी होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है।

जेनेटिक | कुछ लोगों को फैटी लिवर डिसीज की संभावना जींस से मिलती है। परिवार में अगर माता या पिता में से किसी को फैटी लिवर की समस्या रहती है तो ये बच्चे में भी ट्रांसफर होने की संभावना रहती है।

फैटी लिवर से इस तरह कर सकते हैं बचाव

- हेल्दी रहने के लिए शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। अगर लिवर के फैटी होने के जरा से भी संकेत बॉडी दे रहा है तो फौरन डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है।
- हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड्स को खाएं। जिससे फैट का डिपॉजिट लिवर के आसपास ना हो। शराब, जंकफूड ये शरीर में ट्राईग्लिसरॉइड की मात्रा बढ़ा देते हैं।
- वजन को मेंटेन करने के लिए हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करें। क्रैश डाइट जैसी चीजों को फॉलो करना हार्मफुल है।
- डायबिटीज के मरीजों को लिवर के फैटी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और लिवर का चेकअप भी कराएं। जिससे फैटी लिवर जैसी समस्या से बचा जा सके।

फैटी लिवर के लक्षण

- फैटी लिवर में पेट में दर्द रहता है। पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होता है।
- पेट में सूजन महसूस होती है।
- जी मिचलना, उल्टी लगना, भूख ना लगना फैटी लिवर के बहुत ही कॉमन लक्षण हैं।
- कमजोरी और थकान महसूस होना।
- स्किन का पीला पड़ना
- मतिभ्रम या सोचने में कठिनाई होना
- पेट में पानी जैसा महसूस होना
- स्किन पर रैशेज होना
- चोट लगने पर खून ज्यादा बहना।

नोट : इस खबर में बताए गए सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। इसलिए किसी भी उपचार/दवा/डाइट को अमल करने से पहले डाक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

भारत की जी-20 की अध्यक्षता में एक समावेशी वैश्विक स्वास्थ्य संरचना की आधारशिला रखी गई

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

भारत नई दिल्ली में 18वें जी20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इस परिदृश्य में हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में समावेशी और समग्र सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरचना के निर्माण के लिए ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जोड़ने वाले सेतु की आधारशिला रखी जा चुकी है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा, "हमें अपने नवाचारों का जनकल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें वित्तपोषण के दोहराव से बचना चाहिए। हमें प्रौद्योगिकी की न्यायसंगत उपलब्धता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।"

यह देखकर खुशी होती है कि शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने महामारी के वर्षों के दौरान और उसके बाद से अर्जित सामूहिक ज्ञान के आधार पर कार्य करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है - वास्तविक स्वतंत्रता तभी शुरू होती है, जब पूरी मानवता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। यदि कोई वायरस तबाही मचाने का फैसला करता है और हम इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो समाज किसी भी स्तर की आर्थिक खुशहाली का आनंद नहीं ले सकता है। यह बात, भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श की अंतर्निहित अवधारणा रही है।

मंत्रियों, वरिष्ठ नीति निर्माताओं और बहुपक्षीय एजेंसियों ने स्पष्ट तौर पर भारत की जी20 स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का समर्थन किया है, जो सभी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनकी क्षमताओं की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। इस प्रक्रिया में, हम बात पर एक व्यापक सहमति बनाने में सफल रहे हैं कि भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों को रोकने, इसके लिए तैयार रहने और इसका मुकाबला करने के लिए सामूहिक वैश्विक कार्रवाई ही आगे का रास्ता है और महामारी से उबरने की प्रक्रिया न्यायसंगत होनी चाहिए। स्वास्थ्य पर कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक कार्रवाइयों में शामिल हैं, चिकित्सा उपाय प्लेटफार्म के सिद्धांतों और संरचना पर आम सहमति बनाना, जो टीकों, उपचार, निदान और अन्य समाधानों तक पहुंच से जुड़ी मौजूदा असमानताओं में कमी ला सकता है और जिन्हें स्वास्थ्य संकटों से निपटने में प्रभावी उपाय माना जाता है; डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल, जो देशों की डिजिटल स्वास्थ्य पहल की प्रगति की इस प्रकार सहायता करे कि अपने विशिष्ट संदर्भ में अन्य देशों के लिए समाधान अपनाने में अंतर को कम किया जा सके; इस बारे में अपनी समझ विकसित करना कि जलवायु और स्वास्थ्य एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ताकि विशिष्ट समाधानों को प्राथमिकता दी जा सके; और पारंपरिक औषधियों के हमारे भंडार से जानकारी प्राप्त करना, ताकि हमारे भविष्य का स्वास्थ्य हमारे अतीत के ज्ञान से लाभ उठा सके।

प्रतिरोधी चिकित्सा उपाय प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता : दुनिया भर में कोविड-19 टीकाकरण और नैदानिक चिकित्सा ने हमारी निहित असमानताओं को उजागर किया है, जिन्हें हमें दूर करना होगा। आपस में अत्यधिक जुड़ी हुई दुनिया में, किसी देश में रोगाणुओं का खतरा, पूरी दुनिया के लिए खतरा है और हमें सिद्धांतों तथा एक वैश्विक संरचना पर सहमत होना चाहिए, जो टीकों, नैदानिक परीक्षणों, दवाओं और अन्य समाधानों तक न्यायसंगत और समय पर पहुंच में सभी देशों को सक्षम बना सके।

ऐसा वैश्विक प्लेटफार्म समावेशी होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह उन देशों को ध्यान में रखता है, जो समाधान तक पहुंच में बाधाओं का सामना करते हैं; कुशल होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह मौजूदा क्षमताओं और नेटवर्क पर तेजी से आगे बढ़ता है; कार्यकुशल और अनुकूल होना चाहिए; जिसका अर्थ है कि इसमें बदलती जरूरतों और वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार तेजी से अनुकूलन करने के लिए अंतर्निहित लचीलापन है; और जवाबदेह होना चाहिए; जिसका अर्थ है कि एक पारदर्शी संरचना में स्पष्ट और साझा जिम्मेदारी है। इसे शीघ्रता से किफायती चिकित्सा समाधान उपलब्ध कराने चाहिए। जी20 के माध्यम से, हमने डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में ऐसे प्लेटफार्म को लागू करने के परामर्श के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के निर्माण पर बिना किसी देरी के अपनी प्रतिबद्धता जताई है, जहाँ निम्न और मध्यम आय वाले देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, ताकि अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति से मुकाबले के लिए हम पूरे तरह तैयार रहें।

जी-20 देशों ने विशेष रूप से विकासशील देशों में टीकों, चिकित्सीय और नैदानिक उत्पादों की क्षेत्रीय

डॉ. मनसुख मांडविया
(केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री)

विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ सामूहिक रूप से अनुसंधान एवं विकास के एक इकोसिस्टम को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि स्वास्थ्य-आपातकालीन स्थितियों में बाजार की विफलताओं से बचा जा सके।

डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल का शुभारंभ : सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में, डिजिटल स्वास्थ्य सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक के रूप में उभरा है। महामारी के दौरान हमने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में डिजिटल उपकरणों की परिवर्तनकारी क्षमता का अनुभव किया है। कोविड-19 के दौरान, डिजिटल जनकल्याण उपायों के रूप में परिकल्पित को-विन और ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से गेम-चेंजर साबित हुए, जिसने एक अरब से अधिक लोगों तक, जिनमें सबसे कमजोर समुदाय भी शामिल थे, टीकों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के तरीके को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना दिया। भारत पहले से ही एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) - तैयार कर रहा है, जो मरीजों को उनके मेडिकल रिकॉर्ड का संग्रह करने, मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुँच प्राप्त करने और उचित उपचार व अनुवर्ती चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ मेडिकल रिकॉर्ड साझा करने का अधिकार देता है।

120 से अधिक देशों ने अपनी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य नीतियां या रणनीतियां विकसित की हैं, जो कम आय वाले देशों सहित दुनिया भर में डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों की जरूरत को दर्शाती हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक, देशों के पास डिजिटल स्वास्थ्य पहल पर ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कोई आम प्लेटफार्म और भाषा नहीं थी, जबकि वे ऐसा करना चाहते थे। डिजिटल स्वास्थ्य में इस तरह से अलग-अलग से कार्य करने का मतलब है कि समान उत्पाद का कई रूपों में दोहराव होना है। भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत 19 अगस्त को डिजिटल स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल (जीआईडीएच) के लॉन्च के बाद इस स्थिति में बदलाव होना निश्चित है। इस पहल पर जी-20 देशों के सर्वसम्मत समर्थन ने यह सुनिश्चित किया है कि दुनिया, निर्णायक रूप से देशों के बीच बढ़ते डिजिटल-विभाजन को पाटने के लिए, एक विभाजित डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था से वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर आगे बढ़ेगी।

इस पहल का उद्देश्य देशों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करना और मरीजों को गोपनीयता और नैतिकता के उच्चतम सम्मान के साथ जन-केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्राप्त करने में मदद करना है। इस तरह की संरचना को साधन प्रदान करने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर में लोगों को दी जाने वाली डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एक निश्चित मानक पूरा कर रहीं हैं; देशों की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा को समझने और साझा करने के लिए एक मंच बनाया जा रहा है तथा उनकी जरूरतों को इस तरह से उजागर किया जा रहा है कि एक देश दूसरे देश से सीख सकें और सभी के लिए स्वास्थ्य की इस यात्रा की दूरी कम की जा सके।

जलवायु और स्वास्थ्य को प्राथमिकता : सभी क्षेत्रों में जलवायु संबंधी जागरूकता होने के बावजूद, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पौधों के स्वास्थ्य को कवर करने वाले वन-हेल्थ परिदृश्य में जलवायु, स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है तथा इनका आपसी संबंध क्या है, को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। भारत की अध्यक्षता ने पहली बार जी-20 के माध्यम से इन अदृश्य कड़ियों को सुलझाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, ताकि हम समाधानों को प्राथमिकता दे सकें। जी-20 देशों ने निम्न कार्बन उत्सर्जन, उच्च-गुणवत्ता वाले स्थाई और जलवायु सहनीय स्वास्थ्य प्रणालियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र ऐसे समय में पीछे न रह जाये, जब सभी क्षेत्र नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे परिणाम दस्तावेज़ में, जी-20 देशों ने वन-हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से जीवाणु-रोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने का भी वादा किया गया है।

पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका : ऐसे समय में जब दुनिया भर में समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाली एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, तो हमारा मानना है कि शक्तिशाली पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और जी-20 जैसे वैश्विक समूहों के माध्यम से मानवता को उनके अप्रयुक्त लाभों की पेशकश करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले साल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा के डब्ल्यूएचओ-वैश्विक केंद्र का उद्घाटन किया और दुनिया के लिए हमारे प्राचीन आरोग्य ज्ञान के दरवाजे खोले। स्वास्थ्य में साक्ष्य-आधारित पारंपरिक और पूरक चिकित्सा की संभावित भूमिका की पहचान करते हुए हम जी-20 में सदस्य देशों के साथ उस विरासत को आगे ले जा रहे हैं।

एक कालातीत श्लोक के अनुसार, "आरोग्यम परमं भाग्यम्, स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम्", जिसका अर्थ है "निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं।", महामारी के अनुभव के बाद, जी-20 में हमने इस पर ध्यान दिया है और निर्णय लिया है कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है।

भारत आयातक देश से निर्यातक देश बनता जा रहा है : अजय भट्ट

• केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर सोनीपत में आयोजित रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय सशस्त्र बलों के 182 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे। • नीरज चोपड़ा द्वारा दूसरी बार इतिहास रचने पर सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात : अजय भट्ट

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर सोनीपत में आयोजित रोजगार मेले दौरान केंद्रीय सशस्त्र बलों के 182 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। 8वें रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए अजय भट्ट ने कहा कि आज का दिन इन युवाओं के लिए नये जीवन की शुरूआत होगी। उन्होंने कहा कि ये युवा आज से अपना जीवन देश के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का सुनहरा अवसर युवाओं की मेहनत से आया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं को रोजगार देने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि पहले रोजगार देने की कई घोषणाएं हुईं, लेकिन वे पूरी नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे पूरा किया। अजय भट्ट ने नव नियुक्तों से कर्मयोगी पोर्टल का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया, जहां उन्हें प्रशिक्षण से संबंधित ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त होगी।

अजय भट्ट ने कहा कि हम अपने देश के युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने स्वरोजगार के अवसर पैदा किये हैं। अजय भट्ट ने स्किल इंडिया योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से युवाओं को कुशल बनाकर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी कुशलता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भट्ट ने कहा कि कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया गया है और प्रत्येक राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा कि इस कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल अपने नागरिकों का टीकाकरण किया है, बल्कि अन्य देशों को भी टीके भेजे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प से लाखों लोगों की जान बची है। भट्ट ने कहा कि भारत की इस क्षमता को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान्यता दी है। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के बारे में बात करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसे देश में ही बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को अपनी क्षमता से अवगत कराया है और बताया है कि भारत किसी से पीछे नहीं है।

इस मौके अजय भट्ट ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने दोबारा इतिहास रच दिया हैं यह भारतीयों के लिए गर्व की बात हैं। इस अवसर पर, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, सोनीपत के पुलिस उप महानिरीक्षक कोमल सिंह ने नियुक्ति पत्र पाने वाले केंद्रीय सशस्त्र बलों के नए नव नियुक्तों को बधाई दी। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए अजय भट्ट को धन्यवाद दिया।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोहाली में रोजगार मेले के 8वें दौर में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

रोज़गार मेले के 8वें दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई नियुक्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। अपनी शुभकामनाएँ देते हुए, प्रधान मंत्री ने उन्हें एक आशाजनक यात्रा की शुरुआत करते हुए "अमृत रक्षक" की उपाधि दी। मोहाली में, यह कार्यक्रम बीएसएफ पश्चिमी कमान, चंडीगढ़ के मुख्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, और भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) मोहाली परिसर में आयोजित किया गया था।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वावधान में चल रहे इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा व्यक्तिगत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोहाली में 231 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें से 134 को सीमा सुरक्षा बल में, 17 को आईटीबीपी में, 30 को सीआईएसएफ में, 47 को सीआरपीएफ में और 03 को असम राइफल्स में नियुक्त किया गया है।

यह समारोह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री, अनुराग ठाकुर की उपस्थिति से गरिमापूर्ण था, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ठाकुर ने प्रधान मंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की गर्मजोशी से सराहना की और कहा, "हमारे प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता से पैदा हुआ यह रोजगार मेला, सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करने की उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने की दिशा में एक आवश्यक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण हमारे देश की प्रगति

को प्रेरित करता है, और यह मेला युवाओं और देश की समृद्धि के प्रति उनके समर्पण का उदाहरण है।

मंत्री ने युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा शुरू किए गए चल रहे भर्ती अभियान के महत्व पर भी जोर दिया। रोज़गार मेला, इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका लक्ष्य 2023 के अंत तक 10 लाख लोगों तक अपना दायरा बढ़ाना है।

पीवी राम शास्त्री, आईपीएस, विशेष डीजीबीएसएफ पश्चिमी कमान, ने पश्चिमी कमान की जिम्मेदारियों की महत्वपूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए सीमा सुरक्षा और नागरिक सहायता में बीएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। मंत्री ठाकुर ने लखनौर में बीएसएफ परिसर के दौरे के दौरान बीएसएफ कुश्ती, हैंडबॉल और बॉडीबिल्डिंग टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने नीति संवर्धन के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण जुटाए और एथलीटों में दृढ़ संकल्प की भावना जगाई। अपने समापन भाषण में, मंत्री ने 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की प्रगति की सराहना की और नीरज चोपड़ा की उत्कृष्ट उपलब्धियों जैसी उपलब्धियों से प्रेरणा ली।

प्रधानमंत्री का व्यापक दृष्टिकोण - भारत का स्वर्ण युग

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की प्रगति और समृद्धि से जुड़े लंबे समय तक चलने वाले स्वर्ण युग के संबंध में अपने व्यापक दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति दी है, क्योंकि माँ भारती हजारों वर्षों की गुलामी, अधीनता और दरिद्रता के बाद, आत्मविश्वास के साथ फिर से गौरव प्राप्त कर रही है। श्री नरेन्द्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री देश के भविष्य के प्रति बहुत आशान्वित हैं। उनका आत्मविश्वास पिछले नौ साल में प्रगति के लिए किए गए अथक परिश्रम के बाद हुई ठोस प्रगति पर आधारित है।

140 करोड़ देशवासियों के धर्म, क्षेत्र, लिंग, जाति, उम्र या जातीय पहचान के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए ये प्रयास किए गए हैं। मोदी सरकार की प्रत्येक नीति उनके 'सुधार, प्रदर्शन और बदलाव' के मंत्र को दर्शाती है, जो विशेष रूप से गरीबों और वंचितों को लाभान्वित कर रही है। इससे भारत को नौ वर्षों में दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवें पायदान तक पहुंचने में मदद मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इस प्रगति को ठोस आर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार पर अंकुश, सरकारी खर्च में होने वाली चोरी को रोकने, शासन में दक्षता और पारदर्शिता की वृद्धि तथा उदार कल्याणकारी योजनाओं से गति मिली है। महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला विकास बदलाव के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में है- भारत में महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला विकास। जैसा कि पीएम ने कहा, भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में महिला पायलटों की संख्या अधिक है और वे चंद्रयान मिशन जैसे उच्च तकनीक कार्यक्रमों में भी सबसे आगे हैं। यह गर्व की बात है कि लड़कों की तुलना में ज्यादा लड़कियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषय का चयन कर रही हैं। पीएम का लक्ष्य गांवों में 2 करोड़ लाखपति-दीदी बनाना और ड्रोन के संचालन एवं मरम्मत के कार्य में महिलाओं को शामिल करना है। बदलाव की इस यात्रा में मोदी सरकार गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान के जीवन पर्यंत चलने वाले संघर्ष से मुक्ति दिला रही है। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, लगभग 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न, राशन कार्डों की देशव्यापी वैधता, महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने वाले शौचालय, प्रत्येक गांव में बिजली आपूर्ति, रसोई गैस, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य बीमा और किफायती इंटरनेट सेवा की सुविधाएं प्रदान की हैं। आवास उपलब्ध कराने और पाइप से पेयजल की आपूर्ति करने की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मोदी सरकार ने अन्य देशों की तुलना में या पिछली सरकारों की तुलना में मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया है, लेकिन जैसा कि पीएम ने कहा, इन प्रयासों के बावजूद सरकार आत्मसंतुष्ट नहीं है।

देशवासियों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री की लोगों का ध्यान रखने वाली और उनके प्रति संवेदनशील नीतियों के कारण पिछले पांच वर्षों में (2021 तक) 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे हैं और वे मध्यम वर्ग की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। एक सहस्राब्दी तक दु:ख झेलने के बाद, नया भारत आशा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के केन्द्र के रूप में उभर रहा है। देश को बढ़ती युवा शक्ति, महिला शक्ति, मेहनती श्रमिकों और किसानों, प्रतिभाशाली कारीगरों और बुनकरों तथा एक समृद्ध

पीयूष गोयल
(केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री)

सांस्कृतिक परंपरा की संपदा प्राप्त है, जिनके कारण हम दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत का आकांक्षी युवा, मांग और उद्यमशीलता की ऊर्जा पैदा कर रहा है। मोदी सरकार आम लोगों को आवास, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्यान्न प्रदान करने और करोड़ों लोगों को निर्धनता की बेड़ियों से बाहर निकलने में सफल रही है, विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इससे हमारे लघु व्यवसायों और व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यह प्रतिभाशाली युवा पुरुषों और महिलाओं को स्टार्ट-अप बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जो रोज़गार की इच्छा रखने वालों को रोज़गार प्रदाताओं में परिवर्तित कर रहा है। मोदी सरकार की मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत 8 करोड़ नए उद्यमियों को 23 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इनमें से 70 प्रतिशत महिला उद्यमी हैं और 51 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। 140 करोड़ लोगों की शक्ति और आकांक्षाओं पर आधारित भारत का रूपांतरण आज विश्व को दिखाई पड़ रहा है। आज, महामारी और यूक्रेन संकट के दोहरे आघात के बावजूद भारत को अशांत दुनिया में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है।

घबराया हुआ विपक्ष अमृत काल के दौरान आशावाद के इस दौर में, जहां प्रधानमंत्री का दूरदर्शी नेतृत्व भारत को एक विकसित देश बनाएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घबराए हुए हैं। वे तीन बुराइयों : भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और तुष्टिकरण से लड़ने की प्रधानमंत्री की अपील से घबरा गए हैं। उनका डर समझा जा सकता है। सरकार ने प्रभावी कानून प्रवर्तन, प्रौद्योगिकी के उपयोग और पुराने कानूनों - जिनका दुरुपयोग लोगों को परेशान करने और रिश्वत वसूलने के लिए किया जाता था - को समाप्त करने के साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई पहलें की हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अतीत में तुष्टीकरण की नीतियों के विपरीत, जिनसे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा है, हर सरकारी पहल में सभी नागरिकों को समान समझा जाए। प्रधानमंत्री ने वंशवाद की राजनीति की बुराई को सही ढंग से उजागर किया है। राजनीति के इस ब्रांड में, एक विशेष परिवार के सदस्य, जिनके पास योग्यता हो या न हो, के बावजूद, एक राजनीतिक दल के शीर्ष पद पर बने रहते हैं, जबकि एक योग्य पार्टी सदस्य के लिए शीर्ष तक पहुंचने का कोई अवसर नहीं होता है। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प ने जनता को प्रोत्साहित किया है, लेकिन कुछ विपक्षी दल उदास हैं। वे अपनी नकारात्मकता को छिपा नहीं सकते। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। घमंडिया गठबंधन, घोटालों से घिरे वंशवादियों का एक समूह है, जो नियमित रूप से तुष्टीकरण को चुनावी माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता है। इनमें नकारात्मकता, सत्ता की लोलुपता और तीनों बुराइयों के विरूद्ध निर्णायक कार्रवाई के बारे में बढ़ते डर के अलावा कुछ भी समान नहीं है। जब ऐसी पार्टी ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, तो उसे नियमित रूप से लाखों करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन से जुड़े भ्रष्टाचार के घोटालों का सामना करना पड़ा। इस गठबंधन के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि यह गठबंधन की राजनीति की विवशता है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि एक प्रधानमंत्री ईमानदार प्रशासन देने में असमर्थ हो, क्योंकि उसे गठबंधन को बरकरार रखना है। पार्टी को चलाने वाले परिवार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसने उसे बिना किसी जवाबदेही के सत्ता सौंप दी। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए शासन; ईमानदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की ज्वलंत इच्छा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री के लिए परिवार का मतलब भारत के सभी 140 करोड़ लोग हैं, जो उनके संवेदनशील नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा उनको भारत का सबसे प्रभावी और सबसे लोकप्रिय प्रधान सेवक बनाता है।

जाखड़ की प्रधानगी पर सवाल उठाने वाले बताएं सिद्धू को क्यों बनाया था कांग्रेस प्रधान?

• **जालंधर ब्रीज.** विशेष रिपोर्ट

कांग्रेस पार्टी पंजाब में इस समय रोष रैली के नाम पर पार्टी को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। वहीं, स्टेज पर अक्सर इनके नेता मौजूदा सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगा रहे हैं।

परंतु खुद की सरकार द्वारा पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजशाही नीतियों से दुखी होकर और फिर चन्नी के भांजे के घर ईडी द्वारा एकत्रित की गई मोटी रकम ने लोगों को एहसास कराया कि भ्रष्टाचार इन नेताओं के खून में रच चुका है जिसका प्रमाण नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पार्टी प्रधान होते हुए कई बार मीडिया के मंचों से और अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर लोगों को बताया कि माफिया आज भी चल रहा है सिर्फ चेहरा ही बदला है।

जिक्रयोग्य है कि जो लोग सुनील जाखड़ को प्रधान बनाने पर भाजपा को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं वे अपनी ही पार्टी द्वारा भाजपा से आए नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस प्रधान बनाने पर चुप्पी साध ली थी और फिर दबी जुबान में उनके पीछे-पीछे चलना शुरू हो गए थे।

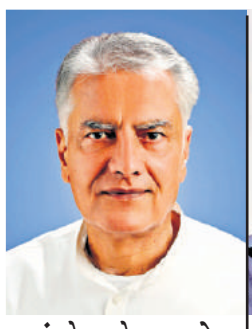

कांग्रेस से गए तो बीजेपी के बने प्रधान

बीजेपी से गए तो बने थे कांग्रेस के प्रधान

अब प्रताप सिंह बाजवा इतना गरज रहे हैं... कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में इनको राज्य सभा मेंबर बनाकर पंजाब की इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से ही बाहर कर दिया गया था और इनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि उनके खिलाफ आवाज बुलन्द कर सकें।

अगर हकीकत में ही सुनील जाखड़ के पल्ले कुछ नहीं तो इनको क्यों परेशानी हो रही है।

2024 और 2027 में लोग फिर एक बार बता देंगे कि पंजाब में वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को ही दोबारा देखना चाहेंगे या किसी और पार्टी के नेता को।

इनको अभी भी नहीं समझ लग रही कि लोगों को अब बेफकूफ बनाना किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान काम नहीं।

जो कहते हैं इस पार्टी का सोशल मीडिया दूसरी पार्टियों से मजबूत है वो भी दिमाग से निकाल दे कि चुनाव सोशल मीडिया जितवाता है। चुनाव तो वो ही जीतेगा जो इलाके के मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगा, पर्चा कल्चर पर रोक लगाएगा और मौजूदा स्थिति के हिसाब से 2024 और 2027 का चुनाव पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर निर्भर होगा।

क्योंकि मानसा वाले झोटे की गिरफ्तारी से नशों के खिलाफ बिगुल बज चुका है और 2024 और 2027 में ये प्रमुख मुद्दा होगा।

अगर मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब पुलिस पर नकेल ना कस पाए तो कुर्सी बचानी उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि विकास कार्यों के काम तो सुखबीर बादल से ज्यादा आज तक किसी ने नहीं करवाए। परंतु नशे और बेअदबी के मुद्दे को ना सुलझा पाने के कारण वो 3 सीटों पर आ गए।

'बिल ले आओ, इनाम पाओ' योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं : डीसी

लोगों को टैक्स कानूनों की पालना का संदेश घर-घर तक पहुंचाने का न्योता

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आज जालंधर के लोगों को मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा टैक्स कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई एक विशेष पहल 'बिल लेआओ, इनाम पाओ' योजना का अधिकतम लाभ उठाने का न्योता दिया।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खरीद समय डीलरों से बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं को खरीद के समय डीलरों से बिल प्राप्त करने के लिए जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगी।

डिप्टी कमिश्नर ने जालंधर वासियों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने फोन पर 'मेरा बिल' ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने का आग्रह करते हुए कहा कि उपभोक्ता 'मेरा बिल' ऐप पर खरीद बिल अपलोड करके लकी ड्रा में भाग ले सकते है तथा बिल का न्यूनतम मूल्य 200 रूपये होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जी.एस.टी पंजीकृत और अपंजीकृत डीलर बिल अपलोड कर सकते है और अपलोड किए गए बिलों से हर महीने की 7 तारीख को लकी ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों और शराब के बिक्री बिल ड्रा के लिए योग्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार प्रदेश में हर माह 290 इनाम दिए जाएँगे तथा प्रत्येक जिले में 10 पुरस्कार दिये जाएँगे। पुरस्कार वस्तु/सेवाओं के लिए चुकाए गए टैक्स के पांच गुना के बराबर होगा लेकिन अधिकतम मूल्य 10 हजार रुपये होगा। उन्होंने कहा कि विजेताओं की सूची टैक्स विभाग की वेबसाइट www.taxation.punjab.gov.in पर सांझा की जाएगी और विजेताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर ने जिलावासियों को इस योजना का अधिक से अधिक हिस्सा बनने का न्योता देते हुए कहा कि टैक्स कानूनों के पालन का संदेश घर-घर तक पहुंचाया जाए।

अनसुलझी चिंताओं को उजागर करती है पीसीएस अधिकारियों की मुख्य सचिव से तत्काल अपील

वेतनमान की असमानताओं, ग्रुप ए की सेवाओं से इनकार और कैरियर की धीमी प्रगति पर प्रकाश डालता है पीसीएस एसोसिएशन का पत्र

जालंधर ब्रीज. अपनी दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक साहसिक कदम में, पंजाब सिविल सर्विस (ई.बी.) ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को एक तत्काल पत्र भेजा है, जिसमें उन गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है जो पीसीएस कैडर को परेशान कर रहे हैं। यह पत्र वेतनमान में असमानताओं से लेकर युवा अधिकारियों के लिए ग्रुप ए सेवाओं से इनकार तक की चिंताओं को सामने लाता है, और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पत्र, लंबित मांगों की एक मार्मिक याद दिलाता है, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री की मौखिक प्रतिबद्धताओं और लिखित निर्देशों के बावजूद, सरकार के कार्य उम्मीदों से कम हैं। पीसीएस एसोसिएशन ने सहमत उपायों के कार्यान्वयन की कमी पर अपनी बढ़ती निराशा व्यक्त की है। मामले के मूल में हाल ही में युवा पीसीएस अधिकारियों को ग्रुप ए की सेवाएं देने से इनकार किया गया है। यह कदम, जो स्पष्ट रूप से

वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने से जुड़ा हुआ है, विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में अधिकारियों की गतिशीलता और प्रतिनियुक्ति की संभावनाओं को सीमित करने की धमकी देता है। यह सीधे तौर पर स्थानीय प्रतिभाओं को पोषित करने और अपने स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के राज्य के घोषित दृष्टिकोण का भी खंडन करता है।

पत्र से एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन यह है कि पिछले प्रशासन के दौरान क्लास ए अधिकारियों को क्लास बी में अपग्रेड किया गया था। औपनिवेशिक मानसिकता को प्रतिबिंबित करने वाले इस कदम ने अपने युवाओं और उनकी आकांक्षाओं के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीसीएस एसोसिएशन का तर्क है कि यह प्रतिगामी कदम पंजाब के सांस्कृतिक मूल्यों को कमजोर करता है और उस प्रगति को खतरे में डालता है जिसे वह हासिल करना चाहता है। एक और प्रमुख चिंता जो उजागर हुई वह वेतनमान में स्पष्ट विसंगति है। जबकि छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पीसीएस अधिकारियों का स्तर अन्य राज्यों के बराबर है, लेकिन उनका प्रारंभिक वेतनमान काफी कम है। यह विसंगति समता और निष्पक्षता पर सवाल उठाती है, जिससे अधिकारी हतोत्साहित हो जाते हैं और उनकी भविष्य की संभावनाओं पर ग्रहण लग जाता है। इसके अलावा, पत्र सुनिश्चित करियर प्रगति की सख्त आवश्यकता पर जोर देता है, एक ऐसा मुद्दा जो लगातार अपील के बावजूद अनसुलझा है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि बांटने की प्रक्रिया तेज़ : जिम्पा

राहत कामों से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा की घड़ी सरकार का डटकर साथ देने की अपील

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि बाँटने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक राहत राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान चाहते थे कि अलग-अलग मदों के अंतर्गत राहत राशि बढ़ाई जाये परन्तु केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक स्वीकृति न मिलने के बाद अब ज़िला स्तर पर राहत राशि बाँटने का कार्य तेज़ कर दिया है।

जिम्पा ने बताया कि फसलों के नुकसान सम्बन्धी अभी मुकम्मल रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई परन्तु जहाँ-जहाँ से गिरदावरी रिपोर्ट मिल रही है, उन जिलों में राहत राशि बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 16 जिलों को 186.12 करोड़ रुपए की राशि 21 अगस्त को जारी की थी।

इस राशि में से 30 अगस्त तक 6 करोड़ 78 लाख 69,369 रुपए बाँटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने धान की खराब हुई पनीरी का 6800 रुपए प्रति एकड़ का मुआवज़ा दिया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान राज्य में 68 लोगों की जान गई थी जिनमें से 62 लोगों के पारिवारिक सदस्यों को प्रति मानव 4 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। इसी तरह अलग-अलग जिलों में से 545 घरों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट मिली थी जिनमें से 306 घरों को प्रति घर 1.20 लाख रुपए मुआवज़ा राशि दी जा चुकी है। इसी तरह 3752 मामूली रूप में क्षतिग्रस्त हुये घरों में से 2514 घरों को बनती मुआवज़ा राशि दी जा चुकी है।

जिम्पा ने बताया कि पशुधन के नुकसान की पूर्ति के लिए भी मुआवज़ा राशि दी जा रही है। बाढ़ के कारण राज्य में कुल 155 भैंसों-गायों की जान जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 99 पशुओं का प्रति पशु 37, 500 रुपए के हिसाब से मुआवज़ा दे दिया गया है। इसी तरह पोल्ट्री धंधे में 14821 जानवरों में से 14520 का बनता मुआवज़ा दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को हिदायतें दी गई हैं कि मुआवज़ा राशि हकदार लोगों को पूरी पारदर्शी और परेशानी रहित दी जाये। उन्होंने बताया कि यह भी निर्देश हैं कि मुआवज़ा देने सम्बन्धी कोई सिफ़ारिश या प्रभावशाली लोगों का पक्ष न लिया जाये और सिर्फ़ सही व्यक्ति को मेरिट के आधार पर मुआवज़ा दिया जाये। जिम्पा ने कहा कि आने वाले दिनों में बाकी मुआवज़ा राशि भी तेज़ी से बाँटी जायेगी और यदि उक्त फंडों के इलावा अतिरिक्त राशि की ज़रूरत पड़ी तो पंजाब सरकार के पास फंडों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने राहत कामों से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपील की है कि इस आपदा की घड़ी सरकार का डटकर साथ दिया जाये।

शिक्षा मंत्री बैंस द्वारा सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण

शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में और सुधार लाने के लिए विचार-विमर्श

• **जालंधर ब्रीज.** लुधियाना

शिक्षा मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस द्वारा विभिन्न सरकारी स्कूलों का औचक निरिक्षण करते हुए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में और सुधार लाने संबंधी विचार-विमर्श किया गया। शिक्षा मंत्री बैंस की तरफ से शहीद सुखदेव थापर कन्या सी. सैक. स्कूल, भारत नगर का दौरा किया और पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के अधिकारियों को कहा कि स्कूल के सौंदर्यकरण और नवीनीकरण के लिए नये डिज़ाइन तैयार किये जाएं। इसके बाद उन्होंने सरकारी हाई स्कूल और सरकारी प्राइमरी स्कूल, सराभा नगर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में बच्चों को आ रही मुश्किलों संबंधी जानकारी ली और उनको हर संभव सहयोग देने भरोसा दिया। बाद में, कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की तरफ से सरकारी प्राइमरी स्कूल और सरकारी हाई स्कूल, सुनेत का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही राज्य निवासियों से वायदा किया था कि शिक्षा के मानक को और ऊँचा उठाया जायेगा, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाकर विद्यार्थियों को सुनहरी भविष्य दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नौजवान पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है और इनकी पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, जिससे वह एक बेहतर पंजाब और समाज का निर्माण कर सकेंगे।

'आप' ने पंचायत भंग करने का फैसला वापस लिया, बाजवा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब सरकार द्वारा पंचायतें भंग करने के फैसले को वापस लेने के मद्देनजर पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को कहा कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की जीत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि आप सरकार को ऐसे अलोकतांत्रिक फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनौती दी थी। पंजाब कांग्रेस ने भी इस अतार्किक फैसले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कई मंचों पर इस मुद्दे को उठाया। बाजवा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की जिसने नकली क्रांतिकारियों (आप) को अपना लापरवाह निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है जो सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती है, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। इसलिए आम आदमी पार्टी को लोकतांत्रिक मूल्यों से छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।

'ग्राम पंचायतों की बहाली लोकतंत्र की जीत'

जालंधर ब्रीज. जालंधर : मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा संविधान का उल्लंघन कर पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों को भंग करके उनके अधिकार छीनने को लेकर यह मामला माननीय अदालत में जा पहुँचा, जिसको लेकर आज माननीय अदालत ने पंजाब सरकार के फैसले को खारिज करते हुए सभी ग्राम पंचायतों को फिर से बहाल कर दिया गया है। भाजपा पंजाब के प्रदेश महासचिव राजेश बाघा ने माननीय न्यायालय द्वारा सुनाये फैसले पर इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। उन्होंने पंचायत संस्थाओं के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पंचायतों को भंग करने का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक था।

वायकॉम 18 ने टीवी और डिजिटल दोनों अधिकार किए हासिल

मुंबई. भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैचों के प्रसारण अधिकार को हासिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की तरफ से ई-नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। इसमें टीम इंडिया के अंतरराष्ट्रीय घरेलू मैचों के टीवी और डिजिटल प्रसारण अधिकार को इस बार वायकॉम 19 ने हासिल किया है। इसी के साथ अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी घरेलू वनडे सीरीज से इस अनुबंध की शुरुआत हो जाएगी। टीम इंडिया के मैचों के मीडिया राइट्स हासिल करने में डिज्नी स्टार भी रेस में थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। टीम इंडिया के घरेलू मैचों के प्रसारण का अधिकार इससे पहले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास था जो पिछले 11 सालों से लगातार इन अधिकारों को हासिल किए हुए थे। अब वायकॉम 18 ने उन्हें मात देते हुए टीवी के साथ डिजिटल में भी राइट्स हासिल किए। इसको लेकर क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार वायकॉम ने 67.8 करोड़ रुपए एक मैच को लेकर बोली लगाई है, जो पिछली बार के मुकाबले 7.8 करोड़ रुपए अधिक है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर महीने में होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के साथ शुरू होने वाले इस अनुबंध में वायकॉम 18 को अगले 5 सालों में टीम इंडिया के 88 अंतरराष्ट्रीय मैचों को दिखाने का मौका मिलेगा। 5,963 करोड़ रुपए में हुआ यह अनुबंध साल 2028 के मार्च महीने में समाप्त होगा। अब टीम इंडिया के घरेलू मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा एप पर होगी। बीसीसीआई से मीडिया राइट्स अगले 5 साल के लिए हासिल करने के साथ वायकॉम 18 के पास अब कई और स्पोर्ट्स इवेंट के प्रसारण अधिकार हैं। इसमें आईपीएल का डिजिटल प्रसारण अधिकार, विमेंस प्रीमियर लीग के टीवी और डिजिटल अधिकार, साल 2024 से साउथ अफ्रीका के घरेलू मैचों के भारत में प्रसारण अधिकार, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, साउथ अफ्रीका टी20, एनबीए, सीरीज ए के प्रसारण अधिकार हैं।

डिप्टी कमिश्नर द्वारा गांव राजेवाल के नजदीक धूसी बांध का निरीक्षण

ग्रामीणों, धर्मगुरुओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, मिट्टी के 50 हजार बोरे उपलब्ध करवाए गए

• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला

डिप्टी कमिश्नर कैप्टन करनैल सिंह संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कल नजदीकी गांव राजेवाल में ब्यास नदी के धूसी बांध के टूटने के मद्देनजर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आज पहुंचे और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन करनैल सिंह ने ग्रामीणों और धार्मिक नेताओं का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने लगातार प्रशासन का सहयोग कर बांध को टूटने से बचाया।

उन्होंने कहा कि फिलहाल बांध को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है और प्रशासन ने मिट्टी से भरी 50 हजार बोरियां उपलब्ध करा दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और ड्रेनेज विभाग के अधिकारी लगातार अभियान की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति को उचित ढंग टहल किया जा सके। लोगों से बातचीत के बाद डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, ऐसे में भूस्खलन स्थल पर तटबंध मजबूत होने से स्थिति और भी बेहतर होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि पानी के तेज बहाव के कारण धूसी बांध करीब 200 मीटर तक टूटने लगा था, जिसे समय रहते ग्रामीणों व धार्मिक संगठनों के सहयोग से संभाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने चल रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को अपने कर्मचारियों के साथ पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया। इस अवसर पर एस.डी.एम लाल विश्वास बैंस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.